साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 9, अंक : 5 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 20 सितंबर 2023 से 26 सितंबर 2023 पेज : ७ कीमत : 3 रुपये

जलवायु परिवर्तन के कारण एशियाई पारिस्थितिकी तंत्र में हुआ भारी बदलाव

नई दिल्ली। 3.4 करोड़ साल पहले अचानक जलवायु परिवर्तन के कारण मध्य एशिया में पारिस्थितिक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। रेगिस्तान तराई में फैल गए, और जैव विविधता स्थायी रूप से प्रभावित हुई। यह अध्ययन एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय, स्टॉकहोम विश्वविद्यालय और सीएनआरएस (फ्रांस) के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा किया गया है।

इस अध्ययन में एशिया से वनस्पतियों और जलवायु के आंकड़ों के साथ-साथ जीवाश्म पराग (पौधों की प्रजनन सामग्री) को जोड़ा गया है। इससे जलवायु और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में तेजी से बदलाव के कारण 3.4 करोड़ साल पहले एक पारिस्थितिक तबाही का पता चला। मंगोलिया, तिब्बत और उत्तर-पश्चिमी चीन के बड़े क्षेत्र बहुत कम वनस्पति के चलते रेगिस्तान बन गए। बड़े जानवरों की जगह छोटे जैसे चूहा गिलहरी आदि कतरने वाले स्तनधारी आ गए। अब रेगिस्तान एक बार फिर पूरे क्षेत्र में तेजी से विस्तार कर रहे हैं, आशंका है कि ये नए पारिस्थितिक तबाही का संकेत दे रहे हैं। यह अध्ययन साइंस एडवांस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। डॉ. नताशा बारबोलिनी ने कहा परिणाम भविष्य की जैव विविधता, कृषि, और मानव भलाई के लिए हैं। डॉ. नताशा एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में पैलेओकोलॉजी में प्रमुख शोधकर्ता हैं। अतीत के साक्ष्य हमें दिखाते हैं कि यदि भूमि का रेतीला होना (मरुस्थलीकरण) जारी रहा तो मध्य एशियाई क्षेत्र अपनी अनूठी जैविक विविधता को फिर कभी वापस नहीं पा सकेगा। अध्ययन इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) के मॉडल अनुमानों का अनुसरण करता है। हाल के जलवायु रिकॉर्ड दिखाते हैं कि एशिया तेजी से ग्रह पर सबसे गर्म और शुष्क स्थानों में से एक बन रहा है। जलवायु परिवर्तन जैसे कि 3.4 करोड़ साल पहले देखा गया था, एक बार फिर से जैव विविधता के नुकसान का कारण बन सकता है।

प्राचीन जलवायु परिवर्तन और पर्वत निर्माण एम्स्टर्डम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डायनेमिक्स के सह-प्रमुख और एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कैरिना होओर्न ने कहा कि 4.3 करोड़ वर्षों के विकास ने हमें इन पारिस्थितिक तंत्रों को पूरी तरह से नए तरीके से समझने का अवसर दिया है। भले ही कुछ पौधे जो विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकते थे, आज भी इस क्षेत्र में मौजूद हैं, वे पहले की अपेक्षा कम दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि आबादी को तेजी से जलवायु परिवर्तन द्वारा स्थायी रूप से बदला जा सकता है।

अध्ययन में पाया गया कि आधुनिक एशियाई जैव विविधता को इन प्राचीन जलवायु परिवर्तनों द्वारा आकार दिया गया है, लेकिन पहाड़ों के निर्माण और तिब्बती पठार का गठन भी इसमें शामिल है। आज मध्य एशिया कुछ सबसे पुराने रेगिस्तानों का घर है, साथ ही साथ यहां हिमालय के बाहर सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। इस भूवैज्ञानिक और जलवायु विविधता ने प्रजातियों की एक आश्चर्यजनक संख्या उत्पन्न की है जो इस क्षेत्र को घर कहते हैं। लेकिन अब लगभग आधे अरब लोगों के साथ-साथ वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन से ये प्रजातियां खतरे में हैं, जिनका जीवित रहना मुश्किल हो रहा है। सूखे से फसलें तबाह हो रही हैं, और रेत के बढ़ते समुद्र देशी पशुओं को चराने के लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर रही हैं।

मरुस्थल में खो गई जड़ी-बूटियां एम्बर वुटरसन ने बताया कि जड़ी-बूटी तब ही सामने आए थे, जब लगभग 1.5 कोरोड़ साल पहले जलवायु अस्थायी रूप से गीली थी। इससे पहले यह बहुत सूखी थी। वुटरसन, एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय कै इंस्टीट्यूट ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डायनेमिक्स के सह-प्रमुख शोधकर्ता हैं। उन्होंने आगे कहा हमारे परिणाम बताते हैं कि एक बार जब भूमि के रेतीला होने (मरुस्थलीकरण) की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो यह तेजी से फैल सकती है और लाखों वर्षों तक रह सकती है। वनस्पति कटाव को रोकती है और पानी और पोषक तत्वों को केंद्रित करती है। मरुस्थलीकरण का कारण वनस्पति का नुकसान होना है।

क्या गरीब देशों को कर्ज के भंवर जाल में फंसा देगा क्लाइमेट फंड?

मुंबई। पहले से ही जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे विकाशील देशों के लिए क्लाइमेट फाइनेंस एक नई समस्या बनता जा रहा है7 लम्बे समय से जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले खतरों जैसे बाढ़, तूफान, सूखा, भुखमरी से निपटने के लिए यह देश अमीर देशों से मदद लेते आए हैं। वहीं मदद के नाम पर दिया जा रहा यह फण्ड इन देशों को कर्जदार बना रहा है, जिसको चुका पाना अपने आप में एक बड़ी समस्या है। हाल ही में अंतराष्ट्रीय संस्था ऑक्सफेम ने इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें क्लाइमेट फाइनेंस पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट फाइनेंस के नाम पर अमीर देशों और विभिन्न संस्थानों द्वारा विकासशील देशों को करीब 4,40,637 करोड़ रुपए (60 बिलियन डॉलर) का वित्त दिया गया था, पर सच्चाई यह है कि उन देशों के पास इसका करीब एक तिहाई ही पहुंच पाया था।

उत्तराखंड में बढ़ती आपदाएं, विशेषज्ञों ने सरकारी लापरवाही को जिम्मेवार ठहराया

मुंबई। दून विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी ने जलवायु परिवर्तन, बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार मशीनरी की तैयारियों का अध्ययन करने के लिए एक राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर पर्यावरणविद् एवं हेस्को के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में जो रहा है, वो कॉमन्स की त्रासदीहै। उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्र के निवासियों के बेहतर भविष्य के लिए पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था को मिलकर काम करना होगा।

आईएएस (सेवानिवृत्त) एवं हिमालयन ट्रस्ट के सचिव अनिल बहुगुणा ने कहा कि पहले जहां राज्य में सरूपगढ़ और नंदप्रयाग प्राथमिक आपदा-प्रवण क्षेत्र थे, लेकिन अब, अव्यवस्थित और अनियमित विकास के कारण, कई पहाड़ी क्षेत्र आपदाओं के प्रति संवेदनशील हो गए हैं। बहुगुणा ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य की राजधानी देहरादून के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने में सरकार विफल रही है, ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रभावी योजनाएं विकसित करने की उसकी क्षमता पर संदेह है। उन्होंने एक सरकारी सलाह का भी उल्लेख किया, जो 25 डिग्री से अधिक ढलान पर निर्माण पर रोक लगाती है, लेकिन राज्य में कई ऐसे निर्माण दिखाई देते हैं, जो 25 डिग्री से अधिक ढलान पर हैं। उन्होंने सलाह दी कि हिमालयी क्षेत्र में स्थानीय समुदायों को आपदाओं को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पूर्व जीएम (सिविल) डी.के. गुप्ता ने नए पहाड़ी शहरों और बस्तियों के नियोजित और सतत विकास के बारे में बात की। उन्होंने न्यू टिहरी शहर का उदाहरण दिया, जिसकी योजना, डिजाइन और विकास लगभग 30 साल पहले यूपी शासन के दौरान किया गया था। उन्होंने बताया कि उस समय नई टिहरी में निर्माण किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया गया, भूकंप के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं थी। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद टीएचडीसीआईएल से टाउनशिप का कब्जा ले लिया है, अब सभी मानदंडों का उल्लंघन किया जा रहा है। बहुमंजिला निर्माण की अनुमति दी जा रही है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक पीयूष रौतेला ने आपदा तैयारियों के उद्देश्य से दस दिवसीय कार्यशालाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। रौतेला ने कहा कि देहरादून अपने भौगोलिक केंद्र के कारण उत्तराखंड में सबसे अधिक आपदा-प्रवण क्षेत्र है, लेकिन दुर्भाग्य से, लोग आपदाओं के अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में अवसरों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने छात्रों के लिए भूकंप इंजीनियरिंग की शिक्षा की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए इसकी तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जलवायु और राज्य की वहन क्षमता के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया। सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में, उत्तराखंड में 14,141 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र में वनों की कटाई देखी गई है, जो हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल विपरीत है, जहां यह आंकड़ा 54त्न से कम है, और अरुणाचल प्रदेश, जहां यह है उत्तराखंड की तुलना में यह 42त्न से भी कम है। नौटियाल ने इसरो की हालिया रिपोर्ट का उदाहरण दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि हिमालयी राज्यों में वन क्षेत्र कम हो गया है, जहां उत्तराखंड इस सूची में सबसे ऊपर है और यह राज्य के अंधकारमय भविष्य के लिए एक चेतावनी संकेत है। दून विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कुसुम अरुणाचलम ने प्रकृति के नुकसान को कम करने के साधन के रूप में कृषि वानिकी की अवधारणा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इस विडंबना की ओर इशारा किया कि देहरादून, कई नीति-निर्माण संस्थानों का घर होने के बावजूद, अभी भी प्रभावी नीति निर्माण में चुनौतियों का सामना कर रहा है। दून विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ममगाईं ने एक पहाड़ विशिष्ट एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) विकास नीति की आवश्यकता को रेखांकित किया, इस बात पर जोर दिया कि इसे कहीं और से अंधाधुंध रूप से नहीं अपनाया जाना चाहिए, बल्कि राज्य की अनूठी जरूरतों के अनुरूप सक्रिय रूप से तैयार किया जाना चाहिए। दून विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुनीत नैथानी ने कहा कि जहां केवल 15,000 कार्बन फुटप्रिंट की सीमा होनी चाहिए, इस क्षेत्र में रातों रात 300,000 से अधिक कार्बन फुटप्रिंट का अनुभव होता है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने ग्राम आपदा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन और राज्य के लिए एक स्थायी योजना के विकास का प्रस्ताव रखा। उन्होंने जोशीमठ और औली जैसे स्थानों में अपनाई जा रही विकास रणनीतियों पर असहमति व्यक्त की। सम्मेलन का समापन करते हुए दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने पर्यावरणीय आपदा और अस्थिरता की कीमत पर उत्तराखंड में लागू किए जा रहे विकास मॉडल के बारे में कुछ प्रासंगिक सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चार-धाम यात्रा के कारण पूरे राज्य में पहाड़ों की अवैज्ञानिक एवं अविवेकपूर्ण कटाई के कारण संकट उत्पन्न हुआ। यह समझना मुश्किल है कि सरकार से अनुरोध किसने किया है। एक ऐसा हाईवे तैयार करना जो दिल्ली-देहरादून को ढाई घंटे में कवर करेगा। किसी भी उत्तराखंडी ने कभी इस सुविधा की मांग नहीं की, जबकि शहर की सड़कें वैसे ही भीड़-भाड़ वाली रहती हैं। भविष्य में आपदाओं से बचने के लिए जो भी विकासात्मक मॉडल लागू किया जाए, इसका वैज्ञानिक और टिकाऊ आधार पर उचित जांच की जानी चाहिए। उन्होंने हिमालय क्षेत्र को अत्यधिक खड़ी ढलानों पर काटने की प्रथा की आलोचना की, जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है।

मुख्यमंत्री निवास में गणपति की स्थापना और पूजा अर्चना

भोपाल मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर परिवार के साथ भोपाल के प्लेटिनम प्लाजा के पास मूर्तिकार श्री रवि प्रजापति द्वारा निर्मित विघ्नहर्ता गणपति जी की प्रतिमा लाकर निवास में प्रतिष्ठापित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह, पुत्र श्री कार्तिकेय सिंह चौहान उपस्थित थे। मुख्यमंत्री निवास में विधि विधान पूर्वक गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सपरिवार भगवान गणेश की पूजा अर्चना की।

मानदेय भुगतान के लिए पर्यावरण मित्रों का कार्यबहिष्कार जारी

देहरादून नगर निगम कार्यालय परिसर श्रीनगर में सोमवार को तीसरे दिन भी आउटसोर्स पर्यावरण मित्रों का धरना जारी रहा। कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप सफाई कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है। साथ ही एक संस्थान में सेवारत होने के बावजूद एक समान कार्य के लिए एक समान मानदेय नहीं दिया जा रहा है।

रोहित कुमार, हरिओम, रंजीत व विकास ने कहा कि आउटसोर्स के माध्यम से नगर निगम श्रीनगर में 36 पर्यावरण मित्र सेवारत हैं। इन कर्मचारियों को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से मानदेय नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीते तीन साल से समस्त आउटसोर्स पर्यावरण मित्रों के ईपीएफ व ईएसआई का लेखा-जोखा भी नहीं दिया जा रहा है। कार्य बहिष्कार करने वालों में देशराज, अजय, कल्पना देवी, बबली देवी, मंजू देवी, सविता देवी, बाला देवी,पूजा, गीता, लक्ष्मी, दलीप कुमार, अजय, रतिराम, हरिओम व रमन कुमार आदि शामिल थे।

खतरे में दुनिया के सबसे बड़े फूल रैफलेसिया का अस्तित्व, बचाने के लिए जल्द कार्रवाई की दरकार

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे बड़े और बदबूदार फूल रैफलेसिया का अस्तित्व खतरे में है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पौधे की 42 प्रजातियां ज्ञात हैं, जो सभी खतरे में हैं। हालांकि इसके बावजूद इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) ने केवल एक प्रजाति 'रैफलेसिया मैग्निफिका' को संकटग्रस्त प्रजातियों की लिस्ट में शामिल किया है।

बता दें कि यह फूल अपने बड़े आकार के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आकार में यह फूल तीन फुट तक बढ़ सकता है, जबकि इसका वजन 6.8 किलोग्राम तक होता है। यही वजह है कि यह फूल सदियों से न केवल आम लोगों के लिए बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहा है। इंडोनेशियाई वर्षावनों में पाया जाने वाला यह फूल अपने आकार के साथ-साथ अपनी दुर्गन्ध के लिए भी जाना जाता है। चटक लाल का यह फूल देखने में बेहद खूबसूरत होता है लेकिन साथ ही इससे सड़े मांस के जैसी गंध आती है। यह गंध परागण के लिए मांस खाने वाली मक्खियों और कीटों को आकर्षित करने के लिए होती है। इस गंध की वजह से दूसरे जीव इसके करीब नहीं जाते। सुमात्रा के स्थानीय लोग इसे मुर्दा फूल भी कहते हैं। इंडोनेशिया के अलावा यह फूल मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस में पाया जाता है। देखा जाए तो अपने आप में अनोखा यह फूल एक तरह का परजीवी पौधा है। इसमें दिखाई देने वाली पत्तियां, जड़ें या तने नहीं होते। इसके बजाय, यह पानी और पोषक तत्वों के लिए अपने मेजबान पौधे पर निर्भर रहता है। यह फूल साल के कुछ महीनों में ही खिलता है। इसके खिलने की शुरूआत अक्टूबर से होती है, जो मार्च तक यह पूरी तरह से खिलता है। हालांकि यह फूल बेहद छोटी अवधि के लिए ही खिलता है और बहुत जल्द मुरझा जाता है। रैफलेसिया का जीवन चक्र बेहद रहस्यमय है, और वैज्ञानिक अभी भी इसकी नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं। इन विशिष्ट पौधों के सामने आने वाले खतरों को समझने के लिए, वैज्ञानिकों की एक टीम ने दुनिया का पहला सहयोगी नेटवर्क बनाया है। सुन्दर होने के साथ-साथ यह पौधा औषधीय गुणों की वजह से पारंपरिक चिकित्सा में भी उपयोग किया जाता है। रैफलेसिया पौधों की रासायनिक संरचना ज्यादातर अज्ञात है, हालांकि इसकी कुछ प्रजातियों में टैनिन का उच्च स्तर पाया जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो दक्षिण-पूर्व एशिया के जंगलों का जिस तरह विनाश हो रहा है उसके चलते आज इस फूल का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इस बारे में जर्नल प्लांट्स, पीपल, प्लैनेट में प्रकाशित नए अध्ययन से पता चला है कि रैफलेसिया की कुल 42 प्रजातियां ज्ञात हैं, जो सभी खतरे में हैं। इनमें से 25 प्रजातियों को गंभीर रूप से खतरे में पड़ी प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि 15 प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। वहीं दो को असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया है। रिसर्च से पता चला है कि इस पौधे की दो-तिहाई से अधिक प्रजातियों का संरक्षण नहीं किया जा रहा है। वहीं इन पौधों के कम से कम 67 फीसदी ज्ञात आवास संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं, जो इनके लिए खतरों को और बढ़ा रहा है। बता दें कि यह पहला वैश्विक मूल्यांकन है, जिसमें इस पौधे के अस्तित्व पर मंडराते खतरों को उजागर किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड बॉटैनिकल गार्डन के उप निदेशक और अध्ययन से जुड़े शोधकर्ता डॉक्टर क्रिस थोरोगूड का कहना है कि यह अध्ययन इस तथ्य को उजागर करता है कि पौधों के लिए दुनिया भर में संरक्षण के प्रयास, चाहे वे कितने भी प्रतिष्ठित क्यों न हों, जानवरों के लिए किए जा रहे संरक्षण के प्रयासों के साथ तालमेल नहीं रख पाए हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार रैफलेसिया की प्रजातियां आमतौर पर बहुत सीमित क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिससे वे अपने निवास स्थान के विनाश के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं। अध्ययन से पता चला कि शेष आबादी में से कई के पास बहुत कम संख्या में पौधे हैं और वे ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जो कृषि के लिए वनों क्षेत्रों में होने वाले संभावित बदलावों से सुरक्षित नहीं हैं। चूंकि वनस्पति उद्यान में रैफलेसिया को उगाने के प्रयास बहुत सफल नहीं रहे हैं, इसलिए उनके प्राकृतिक आवासों को तुरंत संरक्षित करना बेहद जरूरी है। ऐसे में शोधकर्ताओं ने भी दुनिया के कुछ सबसे असाधारण फूलों को संरक्षित करने के लिए एक समन्वित, बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है।

गैलाथिया खाड़ी में पड़ाव का राष्ट्रीय महत्त्व

परियोजना के लिए 131 वर्ग किलोमीटर पुरानी वन भूमि सहित लगभग 244 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खाली करना होगा। हालांकि संरक्षणवादियों ने पारिस्थितिकी खतरे को लेकर आगाह किया है जिनमें लुप्तप्राय जीवों, 800,000 पेड़ों की कटाई और स्थानीय जनजातियों (शोम्पेन और निकोबारी) पर पड़ने वाले प्रभाव भी शामिल हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा नियुक्त एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति जल्द ही प्रस्तावित परियोजना को कुछ शर्तों के साथ पर्यावरण मंजूरी दे सकती है। सवाल है कि भारत का अपना आईसीटीपी क्यों होना चाहिए? ट्रांसशिपमेंट एक जहाज का माल या कंटेनर दूसरे जहाज में भेजने का पड़ाव होता है। यह तब होता है जब दो बंदरगाहों के बीच कोई सीधा नौवहन मार्ग नहीं होता है। ट्रांसशिपमेंट के दौरान, कंटेनरों को बीच के बंदरगाह पर उतारा जाता है और फिर अलग जहाज पर लादा जाता है जो अंतिम गंतव्य के लिए रवाना होता है। ट्रांसशिपमेंट आमतौर पर कम कागजी कार्रवाई वाली व्यवस्था है और इसमें अफसरशाही का हस्तक्षेप भी कम होता है। भारत के 75 प्रतिशत ट्रांसशिपमेंट माल का प्रबंधन भारत के बाहर के बंदरगाहों पर किया जाता है। इससे न केवल विदेशी बंदरगाहों को भारत के व्यापार से लाभ होता है बल्कि भारत में विदेशी व्यापार की स्थिति भी मूल्य वृद्धि, ट्रैफिक और कई तरह की अक्षमताओं के कारण बेहद संवेदनशील बनी रहती है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का मकसद लॉजिस्टिक्स लागत को मौजूदा 14 प्रतिशत से घटाकर लगभग 9 प्रतिशत करना है। भारत आने वाले और यहां से जाने वाले कंटेनरों की कुल मात्रा (निर्यात के साथ-साथ आयात) एक वर्ष में लगभग 2 करोड़ टीईयू है। इसमें से लगभग 30 लाख टीईयू ट्रांसशिपमेंट प्रक्रिया के लिए क्षेत्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्रों जैसे कि कोलंबो, सिंगापुर, केलांग (मलेशिया में) और दुबई में से किसी एक से गुजरते हैं। इन 30 लाख टीईयू में से, लगभग 10 लाख टीईयू, भारत के पश्चिमी समुद्री तट के बंदरगाहों के यातायात से संबंधित है और करीब 20 लाख टीईयू पूर्वी बंदरगाहों से संबंधित हैं। इसके अलावा म्यांमार और बांग्लादेश से 10 लाख टीईयू आता है। नए सिरे से ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की कठिनाई यह है कि स्टैंडअलोन ट्रांसशिपमेंट गतिविधि विशेष तौर पर लाभकारी नहीं है क्योंकि इसे मूल या अंतिम गंतव्य पर एक कंटेनर को लादने और निकालने के सामान्य शुल्क का केवल 30 प्रतिशत ही मिलता है। इसके अलावा इसमें दिक्कत यह है कि सुदूर इलाकों के माल का अभाव भी यहां है। ऐसे में भले ही आईसीटीपी अपने संचालन के पहले दशक में प्रति वर्ष 30 लाख टीईयू की मौजूदा उपलब्ध मात्रा का उचित हिस्सा हासिल करने के बाद वृद्धि कर सकता है लेकिन इसके बाद भी यह लंबे समय तक नकदी के स्तर पर नफा न नुकसान की स्थिति में नहीं होगा। समझा जाता है कि सरकार को उम्मीद है कि बोली लगाने वाले विजेता चरणबद्ध तरीके से करीब 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। हालांकि इसमें एक गंभीर वित्तीय चुनौती है। लेकिन इस मॉडल को वाणिज्यिक रिटर्न देने के साथ-साथ भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील स्थान में विकास एजेंडे को बढ़ावा देने में भी सक्षम होना चाहिए। एक तीन-भाग वाले 'विकास-सह-वित्त मुहैया कराने वाला' मॉडल खुद ही इसका सुझाव देता है। यह वास्तव में व्यवहार्यता अंतर (वीजी) फंडिंग, क्षेत्र विकास अधिकार और सार्वजनिक खर्च का संयोजन होगा। 20,000 करोड़ रुपये के चरणबद्ध निवेश अनुमान पर 40 प्रतिशत की वीजी पात्रता से पूंजीगत व्यय का बोझ 8,000 करोड़ रुपये कम हो जाएगा।

मिलेट क्वीन लहरी बाई की प्रधानमंत्री ने की तारीफ, राष्ट्रपति ने दिया सम्मान

मप्र को बनायेंगे मिलेट स्टेट - मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

भोपाल)लहरी बाई पर गर्व है, जिन्होंने श्री अन्न के प्रति उल्लेखनीय उत्साह दिखाया है। उनके प्रयास कई अन्य लोगों को प्रेरित करेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस टवीट के पहले कोई नहीं जानता था कि लहरी बाई कौन है। आज लहरी बाई को मिलेट क्वीन के नाम से सब जानने लगे हैं। यूनेस्को द्वारा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है तब लहरी बाई होने का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है।

मध्यप्रदेश के जनजातीय बहुल जिले डिंडोरी से करीब 60 किलोमीटर टूर बजाग विकासखंड के सिलपीड़ी गांव में रहने वाली 28 वर्षीय लहरी बाई करीब एक दशक से मिलेट्स बेंक चला रही हैं। अपने छोटे से कच्चे घर के एक कमरे में उन्होने विलुप्त प्रजातियों के बीजों का बैंक तैयार किया है। इनमें कई अनाज ऐसे हैं, जिन्हें जानने पहचानने वाले लोग भी नहीं बचे हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने हाल में लहरी बाई को श्रीअन्न प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वर्ष 2021-22 का %पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान% प्रदान किया। लहरी बाई को कृषक अधिकार वैश्विक संगोष्ठी के अलंकरण समारोह में सम्मान स्वरूप 1,50,000 रुपये की नकद राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया।

बीज बैंक में 150 से ज्यादा बीज लहरी बाई के पारंपरिक मिट्टी से बने तीन कमरों के घर में रहती हैं। एक कमरे में उनका परिवार रहता है। दूसरे में घर के अन्य सामान और तीसरे में सामुदायिक बीज बैंक है। इसमें 150 से ज्यादा प्रकार के बीज हैं। लंबे समय तक बीजों की सुरक्षा करने के लिए लहरी बाई ने बड़ी-बड़ी मिट्टी की कोठी भी बनाई है। उनके बीज बैंक में कांग की चार प्रजातियां- भुरसा कांग, सफेद कलकी कांग, लाल कलकी कांग और करिया कलकी कांग । सलहार की तीन प्रजातियां बैगा सलहार, काटा सलहार और ऐंठी सलहार, कोदो की चार प्रजातियां- बड़े कोदो, लदरी कोदो, बहेरी कोदो और छोटी कोदो, मढिया की चार प्रजाति- चावर मढिया, लाल मढिया, गोद पारी मढिया और मरामुठ मढिया, साभा की तीन प्रजाति- भालू सांभा, कुशवा सांभा और छिदरी सांभा, कुटकी की आठ प्रजातियां- बड़े डोंगर कुटकी, सफेद डोंगर कुटकी, लाल डोंगर कुटकी, चार कुटकी, बिरनी कुटकी, सिताही कुटकी, नान बाई कुटकी, नागदावन कुटकी, छोटाही कुटकी, भदेली कुटकी और सिकिया बीज उपलब्ध है। इसके अलावा दलहनी फसल - बिदरी रवास, झुंझुरु, सुतरू, हिरवा और बैगा राहड़ के बीज भी लहरी बाई के पास मौजूद हैं। लहरी बाई आस पास के गांवों के किसानो को ये बीज देती है और फसल आने पर वापस ले लेती है। इस प्रकार वि लुप्त हो रहे बीजों को हर फसल पर नया जीवन मिल जाता है। लहरी बाई के इस प्रयास से दुर्लभ बीजों की रक्षा हो रही है। अब तक 300 से ज्यादा किसानों को अपने बीज बैंक से बीज देकर उन्हें भी बीजों को बचाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। लहरी बाई ने तीन विकासखंडों समनापुर, बजाग और करंजिया के अंदरूनी गांवों में इन्हीं पारंपरिक बीजों की खेती होती है। खास तौर पर किवाड़, चपवार, गौरा, ढाबा, जीलंग, अजगर, लमोठा, धुरकुटा का जामुन, टोला, कांदावानी, तातर, सिलपीढ़ी, डबरा, ठाड़पथरा,पांडपुर, लिमहा, दोमोहनी, केन्द्रा, लदरा, पीपरपानी, बर्थना, कांदाटोला, सैला गांवों में किसान भी इस काम में सहयोग दे रहे हैं। लहरी गांव-गांव जाकर बीज बांटती हैं और फसल आने पर बीज की मात्रा के बराबर वापस ले लेती हैं। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 की घोषणा के तीन साल पहले ही शि व राज सिंह चौहान ने राज्य मिलेट मिशन बनाकर काम शुरू कर दिया था। मध्यप्रदेश में मिलेट आधा रि त खादय पदार्थों और खादय प्रसंस्करण की अपार संभावनाएं हैं। मि लेट उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। डिण्डोरी जिला मिलेट से समृद्ध जिला है। लहरी बाई डिण्डोरी जिले की ब्रांड ऐंबेसेडर हैं।

बारिश के जल को तालाबों में सहेजा और विकसित किए 'ईको पर्यटन केंद्र

इंदौर जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए वृहद स्तर पर चलाए अभियान के सुपरिणाम दिखाई देने लगे हैं। पिछले डेढ़ वर्षों में जिले के ग्रामीण क्षेत्र में करीब 96 नए तालाब विकसित किए गए और 344 का जीर्णोद्धार भी किया गया। ऐसे में इस वर्षाकाल में ये सभी तालाब लबालब हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये तालाब नए रिचार्जिंग पाइंट के रूप में काम कर रहे हैं।

इन तालाबों के विकास व निर्माण कार्य में जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायतों व वाटरशेड कमेटी के सदस्यों का सहयोग भी लिया है। इस वजह से कुछ तालाबों के संरक्षण का जिम्मा वाटरशेड समिति और स्थानीय रहवासी ही उठा रहे हैं। इतना ही, तालाबों के संरक्षण के साथ पिछले एक वर्षा में ग्रामीण क्षेत्र में ईको पर्यटन के केंद्र भी तैयार किए गए हैं। यह कवायद की जा रही है कि लोग इन स्थानों पर घूमने जाने वाले पर्यटक हरियाली व तालाब के साथ बायोडायवर्सिटी को भी देख सके। अमृत सरोवर वाले स्थानों पर 15 अगस्त व 26 जनवरी जैसे मौकों पर पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ ग्रामीण भी अमृत सरोवर वाले स्थानों पर पहुंचकर ध्वजारोहण करते हैं ताकि स्थानीय लोगों का इस स्थान से जुड़ाव बना रहे। जिला पंचायत द्वारा जिले में 7 अमृत सरोवर वन क्षेत्र में तैयार किए गए हैं। इन सरोवरों के बनने से वन्य प्राणियों एवं पशु पक्षियों को अनुकूल पर्यावरण की स्थिति सुलभ हुई है। ग्राम जेतपुरा पेडमी 65 हजार घनमीटर क्षमता का एवं पेडमी गौशाला परिसर में 42 हजार घन मीटर क्षमता का अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। जानापाव पहाड़ी के नीचे ग्राम कुवाली में 45 हजार घनमीटर क्षमता का बनाा गया अमृत सरोवर वन क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रहा है। इसी तरह ग्राम बैंका राजपुरा उमठ के ढेपाला पाला 45 हजार घन मीटर क्षमता का अमृत सरोवर तैयार किया गया है। यह सभी अमृत सरोवर वन क्षेत्र में पर्यटक आकर्षण स्थल व ईको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुए हैं। ग्राम कुलथाना, कालाकुंड एवं राजपुरा में वनक्षेत्र में भी तीन 3 अन्य अमृत सरोवर बनाए गए हैं। जिले में 96 अमृत सरोवर पूर्ण हो चुके हैं। आइआइटी सिमरोल परिसर में केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान की सांसद निधि से स्वीकृत अमृत सरोवर का निर्माण कार्य भी पूर्णता की ओर है। ग्राम शिवनी, देवली एवं जैतपुरा खुर्दा के अमृत सरोवर भी 50 से 75 प्रतिशत तक तैयार हो चुके हैं।

जन औषधि केन्द्रों पर दवाएं 50 से 90 प्रतिशत तक सस्ती

इंदौर प्रधानमंत्री जन-औषधि केन्द्रों के रूप में कमजोर और गरीब नागरिकों के लिये जीवन-रक्षक सौगात मिली है। जन-औषधि केन्द्र पर उपलब्ध दवाइयाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुरूप और उत्तम गुणवत्ता की होती है। साथ ही दवाइयाँ बाजार में मिलने वाली ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में 50 से 90 प्रतिशत तक सस्ती होती हैं। गरीब और कमजोर वर्ग महँगी दवाइयों से परेशान नहीं हो, उन्हें सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिये प्रधानमंत्री जन-औषधि केन्द्र योजना संचालित हो रही

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008